हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़
24 जुलाई 2024, समय 1810

- उच्चतम न्यायालय ने अदालत की कार्य अवधि से संबंधित नियमों में संसोधन किया
- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पासिंग आउट परेड से सलामी ली और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अव्वल रहने वालेपुलिस जवानो को सम्मानित किया
- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ,राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को बंद करने और राज्यवार प्रवेश परीक्षायों को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है
- हरियाणा के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा है कि,उच्तम शिक्षा नीति की बदौलत नागरिकों का सरकारी स्कूलों के प्रति विस्वास और भरोसा बढ़ा है
- जींद जिले के 30 गावों को नशा मुक्त घोषित किया गया

सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत की कार्य अवधि से संबंधित अपने नियमों में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार नई कार्य अवधि सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक होगी। शीर्ष न्यायालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि छुट्टियों और दूसरे तथा चौथे शनिवार को अदालत के कार्यालय बंद रहेंगे। नए नियम एक अगस्त से लागू होंगे

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और परेड की सलामी ली।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रथम रहने वाले सिपाही नरविंद्र कुमार, द्वितीय रहने वाले सिपाही वकील कुमार और तृतीय स्थान हासिल करने वाले सिपाही जगबीर सिंह को सम्मानित भी किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बाद आज 1265 जवान हरियाणा पुलिस में शामिल हो गए। इन जवानों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ भी दिलाई गई। इनमें से 765 जवानों ने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सुनारिया और 500 जवानों ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मधुबन में प्रशिक्षण हासिल किया है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि भर्ती योग्यता के आधार पर पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से की गई

है ।समारोह के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पुलिस जवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि आज के बाद इन जवानों की असली जिम्मेदारी शुरू होगी। श्री नायब सिंह ने उम्मीद जताई कि सभी जवान मेहनत और लगन के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार, हरियाणा पुलिस को अग्रणी पुलिस बनाने के लिए कटिबद्ध है।बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भर्ती रोको गिरोह सक्रिय है। कोई भी सरकारी नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो यह गिरोह अदालत का रुख करता है लेकिन इसके बावजूद पारदर्शी तरीके से युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है।

केंद्र सरकार ने मेडिकल परीक्षा पर विवादों के बीच आज स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा- नीट को बंद करने और राज्य-वार प्रवेश परीक्षाओं को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित प्रशन के उत्तर में दी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – UGC की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि इस वर्ष जून में आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। श्री मजूमदार ने कहा कि अब यह परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर, के बीच कंप्यूटर आधारित होगी।

आज लोकसभा में केन्द्रीय बजट 2024-25 पर बहस की शुरूआत करते हुए कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि यह देश में दिन ब दिन बढती जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार केन्द्र सरकारी विभागों में खाली पडे पदो को भरने के कदम नही उठा रही है। कांग्रेस नेता ने हरियाणा में बेराजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अग्निवीर योजना पर सरकार की आलोचना की और इस योजना को वापस लेने की मांग की। सुश्री शैलजा ने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट में किसानो और श्रमिकों की अनदेखी की है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के बिप्लब कुमार देब ने कहा कि 2014 में जब BJP सरकार सत्ता में आई थी तब भारत पांच कमजोर देशो में था। श्री देब ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक समीक्षा में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि साढे छह से सात प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। उन्होंने केन्द्रीय बजट 2024-25 को देश की आवश्यकताओं पर केन्द्रित बजट बताया। श्री देब ने कहा कि 2023-24 की तुलना में पूजीगंत व्यय 18 प्रतिशत अधिक रखा गया है जिसका मतलब है कि बुनियादी सेवाओं और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है।

हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि उत्तम शिक्षा नीति से नागरिकों का सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ा है।प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में पच्चीस लाख से ज़्यादा विद्यार्थी संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।शिक्षा मंत्री आज नारनौल में आयोजित स्कूल प्रबंधन समिति प्रशिक्षण एवं सम्मेलन में अध्यापकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को मुख्यातिथि के तौर पर संबोधित रही थीं।

उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन समितियां प्रदेश के स्कूलों पर एक समीक्षात्मक दृष्टि रखती हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियां सक्रिय हैं वहां विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर है। इस दौरान स्कूल प्रबंधन समिति प्रशिक्षण को लेकर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई जिसके माध्यम से स्कूल प्रबंधन समिति की पूरी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई।

.....

जींद जिले के 30 गावों को नशा मुक्त गांव घोषित किया गया है।गांव भौंगरा में पंचायत एवं पुलिस प्रशासन की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में हिसार मण्डल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ M.रवि किरन द्वारा इन गावों को नशा मुक्त गावं के सम्मान से नवाज़ा गया ।इस अवसर पर जींद के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार एवं पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे ।मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए डॉ M रवि किरन ने इन गावों को नशा मुक्त बनाने में इन पंचायतों की भूमिका भी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि,पुलिस के प्रयसों से अब तक हिसार मण्डल के लगभग 700 लोगों ने नशे को अलविदा किया है।

****

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने आवेदक को अनुदान जारी करने में देरी करने और अधिसूचित सेवा निर्धारित समय सीमा में न देने के कारण पंचकूला में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में कार्यरत तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक शशिकांत पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता विपिन सरदाना ने 'गत वर्ष जुलाई को परीक्षण उपकरण सहायता' का अनुदान जारी न करने से सम्बंधित शिकायत दी थी। आयोग ने जांच में पाया कि सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बावजूद विभाग द्वारा इस वर्ष 4 जनवरी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जुर्माना उनके जुलाई माह के वेतन से काटा जाएगा। जिसमें से 5 हजार रुपये आवेदक को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे और 5 हजार रुपए राज्य खजाना में जमा करवाकर रसीद सहित आयोग को सूचित किया जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की जेलों के लिए 2 करोड़ 84 लाख रुपये की दवाइयों और चिकित्सा सामग्रियों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सामग्रियों की मांग हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को दवा खरीद के लिए भेजी जा रही है।